

Newspaper Clips December 22, 2012

Hari Bhumi ND 22/12/2012 P10

Veer Arjun ND 22-Dec-12 P-11

सुपर कंप्यूटर बनाएगा आईआईटी दिल्ली

एजेंसी. नई दिल्ली

प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी एनवीडिया ने सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए जरूरी अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के साथ गठबंधन करने की घोषणा की है। इससे 2017 तक देश में एक्सास्केल कंप्यूटिंग लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।

आईआईटी और एनवीडिया में गठजोड़ प्रति सेंकेड करेगा 1000 अरब शुद्ध गणना-कार्य



गौरतलब है कि सरकार का प्रस्ताव देश में सुपर कंप्यूटर से जुड़े बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए बड़े स्तर पर निवेश और एक एक्साफ्लॉप अथवा 1000 पेटाफ्लॉप क्षमता वाले सुपरकंप्यूटर विकसित करने का है। एक पेटाफ्लॉप कंप्यूटिंग क्षमता का अर्थ है प्रति सेंकेड 1000 अरब शुद्ध गणना-कार्य। कंपनी ने एक बयान में कहा कि एनवीडिया और आईआईटी दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से विकसित नई एक्सास्केल अनुसंधान प्रयोगशाला (ईआरएल) से देश को अनुसंधान, परीक्षण और विभिन्न क्षेत्रों में तकनीक के विकास में मदद मिलेगी। यह प्रयोगशाला जनवरी 2013 में आईआईटी दिल्ली परिसर में

शुरू होगी। एक्सास्केल कंप्यूटिंग प्रणाली मौजूदा पेटास्केल प्रणाली के मुकाबले 100 गुणे तीव्र गति से काम करेंगे और इससे जीव विज्ञान, औषधि, ऊर्जा, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में नवप्रवर्तन को गति मिलेगी। आईआईटी दिल्ली के कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर डॉ. सुबोध कुमार ने कहा 'अगली पीढ़ी की समस्याओं के समाधान करने की दृष्टिकोण से एनवीडिया और आईआईटी दिल्ली का सामान नजरिया है। दोनों कंप्यूटिंग के प्रदर्शन को बढ़ाकर एक्सास्केल के स्तर तक ले जाना चाहते हैं।' एनवीडिया इंडिया के प्रबंध निदेशक विशाल धूपर ने कहा 'ईआरएल से भारत को सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।'

सुपर कंप्यूटर के लिए आईआईटी दिल्ली व एनवीडिया में गठजोड़

नई दिल्ली, (भाषा)। प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी एनवीडिया ने सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए जरूरी अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के साथ गठबंधन करने की घोषणा की है। इससे 2017 तक देश में एक्सास्केल कंप्यूटिंग लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि सरकार का प्रस्ताव देश में सुपर कंप्यूटर से जुड़े बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए बड़े स्तर पर निवेश और एक एक्साफ्लॉप अथवा 1000 पेटाफ्लॉप क्षमता वाले सुपरकंप्यूटर विकसित करने का है। एक पेटाफ्लॉप कंप्यूटिंग क्षमता का अर्थ है प्रति सेंकेड 1000 अरब शुद्ध गणना-कार्य। कंपनी ने एक बयान में कहा कि एनवीडिया और आईआईटी दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से

विकसित नयी एक्सास्केल अनुसंधान प्रयोगशाला ईआरएल से देश को अनुसंधान, परीक्षण और विभिन्न क्षेत्रों में तकनीक के विकास में मदद मिलेगी। यह प्रयोगशाला जनवरी 2013 में आईआईटी दिल्ली परिसर में शुरू होगी। एक्सास्केल कंप्यूटिंग प्रणाली मौजूदा पेटास्केल प्रणाली के मुकाबले 100 गुणे तीव्र गति से काम करेंगे और इससे जीव विज्ञान, औषधि, ऊर्जा, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में नवप्रवर्तन को गति मिलेगी। आईआईटी दिल्ली के कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर डॉ. सुबोध कुमार ने कहा, 'अगली पीढ़ी की समस्याओं के समाधान करने की दृष्टिकोण से एनवीडिया और आईआईटी दिल्ली का सामान नजरिया है। दोनों कंप्यूटिंग के प्रदर्शन को बढ़ाकर एक्सास्केल के स्तर तक ले जाना चाहते हैं।' एनवीडिया इंडिया के प्रबंध निदेशक विशाल धूपर ने कहा, 'ईआरएल से भारत को सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।'

आईआईटी दिल्ली से एनवीडिया का गठजोड़

नई दिल्ली। प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी एनवीडिया ने सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए जरूरी अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली के साथ गठबंधन करने की घोषणा की है। इससे 2017 तक देश में एक्सास्केल कंप्यूटिंग लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।

सरकार का प्रस्ताव देश में सुपर कंप्यूटर से जुड़े बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए बड़े स्तर पर निवेश और एक एक्साफ्लॉप अथवा 1000 पेटाफ्लॉप क्षमता वाले सुपरकंप्यूटर विकसित करने का है। एक पेटाफ्लॉप कंप्यूटिंग क्षमता का अर्थ है प्रति सेंकेड 1000 अरब शुद्ध गणना-कार्य। एनवीडिया, आईआईटी दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से विकसित नई एक्सास्केल अनुसंधान प्रयोगशाला से देश को अनुसंधान, परीक्षण और विभिन्न क्षेत्रों में तकनीक के विकास में मदद मिलेगी।

Dainik Jagaran ND 22/12/2012 P11

ट्रक में आइआइटीजेई के प्रश्नपत्र मिलने से हड़कंप

जागरण संवाद केंद्र, मोहननगर : इलाके से एक लावारिस ट्रक में शुक्रवार को आइआइटीजेई-2012 से संबंधित दस्तावेज मिलने से सनसनी फैल गई। ट्रक के चालक व परिचालक के न मिलने से पुलिस में हड़कंप मचा है। पुलिस ने लावारिस मिले ट्रक व उससे बरामद प्रश्नपत्र, उत्तर पुस्तिका, बुकलेट व कुछ कागजात को कब्जे में ले लिया है। शुरुआती जांच में पुलिस इसे कबाड़ बता रही है, लेकिन मामले की जांच कराई जा रही है। दूसरी ओर, ट्रक के मालिक के बारे में ठीक से जानकारी न मिलने ने जांच में मुश्किल आ रही है।

शुक्रवार को मोहननगर के बीएलएस कालेज के गेट के सामने लावारिस ट्रक मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस जांच के बाद ट्रक से 2012 में हुई आइआइटीजेई की परीक्षा के कागज मिले। बड़ी संख्या में ट्रक से प्रवेशपत्र, उत्तर पुस्तिका, प्रवेश परीक्षा की बुकलेट और अभ्यर्थियों के नाम लिखे कागजात बरामद हुए हैं। ट्रक एचआर-55ए-5666 के मालिक का नाम मनमोहन सिंह निवासी फरीदाबाद पता चला, लेकिन पुलिस जांच में यह ट्रक अन्य किसी को बेचे जाने की बात सामने आई है। ट्रक के पहले मालिक ने ट्रक 2005

- ◆ मोहननगर में निजी कालेज के सामने लावारिस ट्रक में मिली उत्तर पुस्तिका और बुकलेट
- ◆ ट्रक चालक व परिचालक के न मिलने से बड़ी मामले की संदिग्धता, पुलिस ने शुरु की जांच

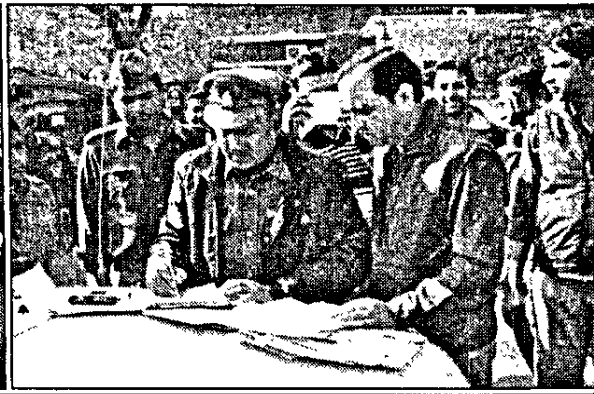
में बेचा था। उसके बाद से ट्रक को तीन पार्टियों को बेचा जा चुका है।

उधर, बड़ी संख्या में ऐसे कागजात मिलने से पुलिस जांच में जुट गई है। ट्रक के चालक व परिचालक के मौके पर न मिलने ने मामले में संदिग्धता पैदा हो गई है।

सवाल यह उठता है कि अगर कागजात बेकार हैं, तो यहां कैसे पहुंचे। ट्रक में सवार चालक व परिचालक कहां हैं। साहिबाबाद थाना प्रभारी का कहना है कि पुलिस ट्रक के मौजूदा मालिक से मिलकर मामले की जांच करने में जुट गई है। शुरुआती तौर पर कागजात कबाड़ प्रतीत होते हैं क्योंकि परीक्षा होने के साथ ही परिणाम भी आ चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

Mahamedha ND 22-Dec-12 P-4

संदिग्ध हालत में मिले आईआईटी के प्रवेश परीक्षा पत्र



से संबंधित प्रवेश परीक्षा पत्र, उत्तर सीट, पहचान पत्र, और मार्किंग सीट से लदा हुआ है। सूचना पाकर घटना स्थल पर पहुंचे साहिबाबाद थाना प्रभारी रामनाथ सिंह यादव ने बताया कि अभी हम मामले की जांच कर रहे हैं कि वास्तविक है क्या और साथ यादव ने बताया कि हमारी टीम संस्थान के अधिकारियों से संपर्क साधने में जुट गई है कि इतने सारे पत्र किस लिये मंगवाए और भेजे जा रहे थे।

मगर सबसे अहम सवाल खड़ा होता है कि अगर सूत्रों की माने तो ट्रक पिछले चार दिनों से मोहन नगर के बीएलएस कॉलेज के सामने लावारिश हालत में खड़ा था मगर किसी ने इसकी शिकायत तक न की और न ही थाना में किसी भी सिपाही ने थाना प्रभारी को भी इसकी सूचना नहीं दी। ये तो गनीमत रही कि ट्रक में कागजात थे और कागजात की जगह कुछ और होता तो साहिबाबाद पुलिस के गले के लिये यह वाहन फांस भी बन सकता था।

साहिबाबाद : ट्रक में लदे प्रश्न पत्र व उत्तर पुस्तिका। दूसरे चित्र में जांच करते थाना प्रभारी रामनाथ सिंह यादव व चौकी प्रभारी धर्मेन्द्र राठौर।

महामेघा

साहिबाबाद (संवाददाता)। ट्रांस हिण्डन क्षेत्र के मोहन नगर करहड़ा रोड के राजीव कोलोनी के निकट एक ट्रक पिछले चार दिनों से खड़ा था मगर किसी ने भी इसकी और सुध नहीं ली। मगर

शुक्रवार की सुबह जब मोहन नगर प्रभारी को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने स्वयं घटना स्थल जांच की तो पता चला कि ट्रक संख्या एचआर 55, ए-5666 जो राजीव कोलोनी के पास बीएलएस

कॉलेज के पास संदिग्ध अवस्था में खड़ा है, जब मोहन नगर चौकी प्रभारी धर्मेन्द्र राठौर ने प्राथमिक जांच की तो पता चला कि इस वाहन में देश के सर्वोच्च टेक्निकल संस्थानों में से एक आईआईटी

Aaj Samaj ND 22.12.2012 P-3

आईआईटी के प्रश्नपत्रों से लदा ट्रक लावारिश मिला

वर्ष 2012 के पुराने प्रश्नपत्र और उत्तर पुस्तिकाएं मिलीं

आज समाज नेटवर्क

गाजियाबाद। जीटी रोड पर मोहन नगर पुलिस चौकी के पास लावारिश हालत में खड़े ट्रक की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब जांच की तो पूरा ट्रक आईआईटी-जेईई-2012 के प्रश्नपत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं से भरा था। बाद में पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया। पुलिस अधिकारी

आईआईटी के दिल्ली कार्यालय से संपर्क कर इसकी जांच कर रहे हैं।

शुक्रवार दोपहर मोहन नगर चौकी के पास जीटी रोड के किनारे एक लावारिश ट्रक खड़े होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच करने पर ट्रक में आईआईटी-जेईई-2012 के प्रश्नपत्र और उत्तर पुस्तिकाएं मिलीं। प्रश्नपत्र देख पुलिस के होश उड़ गए। थाना प्रभारी रामनाथ सिंह यादव ने बताया कि हरियाणा नंबर का उक्त ट्रक लावारिश हालत में मिला है। ट्रक का चालक मौके से फरार है। पुलिस ट्रक के मालिक की तलाश में जुटी हुई

17 जनवरी से मिलेंगे आईटीआई के प्रवेश फार्म

नोएडा। राजकीय, अनुदानित और निजी पॉलीटेक्निक संस्थाओं में संचालित डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग/मैनेजमेंट में प्रवेश के लिए पॉलीटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा पांच से सात मई 2013 तक आयोजित होगी। इसके लिए आवेदन पत्र डाक घरों से 17 जनवरी से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 25 फरवरी है। अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क सहित आवेदन पत्र का मूल्य 250 रुपए और अन्य सभी वर्गों के लिए 400 रुपए तय किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा जिस पॉलीटेक्निक संस्था से आवेदन पत्र खरीदा गया हो, उसी संस्था में स्वयं या डाक के जरिये जमा किया जाएगा।

है। दूसरी ओर दिल्ली स्थित आईआईटी के कार्यालय से भी संपर्क किया जा रहा है। ट्रक

से मिले प्रश्नपत्रों पर आठ अप्रैल, 2012 की तारीख लिखी हुई है।

Indian Express ND 22/12/2012 p-4

New agency set up, HRD set to make accreditation must

EXPRESS NEWS SERVICE

NEW DELHI, DECEMBER 21

THE Human Resource Development Ministry on Friday announced a new accreditation agency under the AICTE and accreditation regulations set to be enforced soon in a bid to make accreditation of educational institutes mandatory.

Currently, institutes can seek accreditation on a voluntary basis. The National Board of Accreditation is the only accrediting agency in the country and is quite overburdened.

With the Accreditation Bill 2010 among the critical education legislations still stuck in Parliament, the ministry appears to be looking at alternative ways to usher in reforms.

Policy makers have for a while been seeking mandatory accreditation of educational

CURRENTLY, institutes can seek accreditation on a voluntary basis

institutes and creation of multiple accrediting agencies to make the process faster. These proposals also feature in the National Accreditation Regulatory Authority for Higher Educational Institutions Bill, 2010.

“There are 3,800 technical institutions, 3,700 management ones, 3,580 polytechnics... over 60,000 courses are offered in these... The new accreditation body will run parallel to the existing National Board of Accreditation with the same set of functions,” HRD Minister Pallam Raju

said. It will be called the Indian Board of Accreditation.

Raju announced that the Distance Education Council, so far under IGNOU, will move under the UGC.

A committee to review distance education in India had recommended that being a regulatory body, the council must be dissociated from IGNOU — the largest distance education provider in the country.

The AICTE has announced that engineering courses will also be available in distance mode and will issue guidelines for the same in March 2013.

Students will be able to opt for engineering courses in distance mode provided their first degree (undergraduate degree/diploma) is through a formal education system.

Accreditation to be must for all higher edu institutes in '13

HRD Min Plans To Make It Mandatory Through Executive Order

Himanshi Dhawan | TNN

New Delhi: Accreditation for all higher educational institutions will be made mandatory from next year. With the National Accreditation Regulatory Authority (NARA) bill hanging fire for the last two years, the human resource development (HRD) ministry is planning to make accreditation mandatory for public and private institutions through executive order to continue with the reform process.

Accreditation will help students assess the quality of programmes and courses, infrastructure and faculty. At present, only about 15% institutions are accredited.

HRD minister MM Pallam Raju said both Universities

Times View

The fact that the government is taking steps to regulate technical and vocational education more rigorously is welcome. Education is a sector that serves a very vital need and families spend huge sums of money in getting their children a decent education. Often, they borrow to put them through a professional course. It is, therefore, absolutely essential that they have some assurance of the quality of education they can expect to get. The real test of the proposed accreditation system, however, will lie in its implementation. It must not be allowed to become just another way for corrupt officials to make money, in the process jeopardizing the future of millions.

Grants Commission (UGC) and All India Council for Technical Education (AICTE) have been tasked with preparing benchmarks for the accreditation process. In fact, the ministry will write to state governments to establish accreditation agencies that will inspect institutions on

these benchmarks.

AICTE has also been asked to set up another accreditation agency — Indian Board of Accreditation — that will assist the existing National Board of Accreditation in inspections of institutions. "There was need felt for a new accreditation body and AICTE will set

up the IBA by February," Raju said.

AICTE has under it 3,800 technical institutions, 3,700 management institutions, 3,500 polytechnics, 240 hotel management institutions and 60 applied art institutions.

These institutions approach AICTE every year for either renewal of their accreditation or for introduction of new disciplines or other expansion plans. There are 60,000 programmes that are accredited under AICTE at present.

Under the NARA bill, existing universities will be given six years to complete the accreditation process while new universities will be allowed to complete teaching two batches of students.

Univs watch out

Accreditation to be made mandatory in a month

FOR REPRESENTATION

By Ritika Chopra In New Delhi

THE Bill on compulsory accreditation of all higher education institutions may not have passed political muster, but that isn't going to put brakes on the government's grand plans.

In fact, accreditation for all public and private universities/colleges (excluding technical institutions) will become mandatory in a month.

The University Grants Commission (UGC) is set to notify a new regulation in this regard in the next 10 days, after which it will be compulsory for existing universities and colleges, which have either completed six years or have educated two batches (whichever is earlier) to apply for accreditation within six months of notification of the regulation.



New Institutes will have to get their preparedness judged in terms of human resources and infrastructure; (left) HRD minister M.M. Pallam Raju.

New UGC regulation to be notified in 10 days

Institutions which haven't completed six years or educated two batches of students will have to apply for accreditation within six months of such completion. New institutes will have to get their preparedness in terms of human resources and infrastructure compulsorily assessed before beginning operation. Currently, accreditation for all UGC-recognised institutes is done by the National Assessment and Accreditation Council.

PENALTIES FOR ERRING UNIVERSITIES

- Recognition of the Institution under Section 12B of the UGC Act will be cancelled
- In case of an erring deemed university, their deemed status can be revoked
- In case of private universi-

"This regulation was passed on December 7 and we have already sent it for notification in the Gazette (of India) after which it will come into force with immediate effect," said Ved Prakash, chair-

man, UGC. This step is clearly a desperate attempt by the human resource development (HRD) ministry to usher in some of the planned reforms which have been stalled in Parliament. HRD minis-

- Grants allocated to erring

ter M.M. Pallam Raju is, therefore, also resorting to the tactic that Sibal employed during his tenure.

- institution will be withheld
- Non-compliant institution will be ineligible for any assistance under general or special assistance programme of UGC
- UGC will publicly announce names of such institutions

Under the UGC Regulation, any institute (private or public) failing to comply can have penalties.

Deccan Herald ND 22/12/2012 P8

AICTE to allow tech education in distance mode from 2013

NEW DELHI: The All India Council for Technical Education is set to allow technical education in distance learning mode from 2013.

Human Resources Development (HRD) Minister M M Palam Raju made an announcement to this effect here on Friday. "A move is on to bring distance education in the country under a proper regulatory frame work and the AICTE will come up with a set of guidelines to conduct technical education in this mode by March next year," he said.

"A regulatory frame work is being worked out to allow tech-

nical education in distance education mode for the first time in the country from next year. Students will be able to pursue courses in all technical subjects, except architecture and pharmacy," AICTE chairman S S Mantha said.

The courses in technical education, however, will not be available to freshers. "A student will be eligible for a BTech course in distance education mode only if he or she has done a diploma in technical subjects from any institution, like the polytechnics. Similarly, a student will be eligible for MTech, if he has done BTech from a

regular engineering college," Mantha said.

This apart, candidates will require a few years of professional experience in their respective fields to apply for the technical courses. A national-level test will be conducted for enrolment, he said. "We are finalising the details."

"Students of distance education will not face any problem in getting jobs as their diplomas or degrees will have the same value as those acquired after undergoing courses in educational institutions," a HRD Ministry official said.

DH News Service